

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति, उत्तरांचल,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून दिनांक : 23 अक्टूबर, 2006

विषय- संरक्षित इमारतों व प्राचीन भवनों के संरक्षण की नई योजना के संबंध में।

महोदय,

चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में उपर्युक्त विषयक नई योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। योजना का आधार दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन द्वारा दी गई संरक्षितियों का अनुपालन करना व भारत सरकार द्वारा Built Heritage के संरक्षण हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति करना है।

इस नई योजना के निम्न प्रकार भिन्न-भिन्न घटक होंगे। योजना के क्रियान्वयन में शहरी विकास विभाग का सहयोग भी प्राप्त किया जायेगा:-

(i) Built Heritage का अभिलेखीकरण।

(ii) Built Heritage का संरक्षण।

(iii) पुरातत्व अन्वेषण।

योजना के इन घटकों का विस्तृत विवरण निम्नांकित है :-

घटक 1 : Built Heritage का अभिलेखीकरण

1. दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन द्वारा बल दिया गया था कि Built Heritage का अभिलेखीकरण शीघ्रातिशीघ्र कर लिया जाये। अभिलेखीकरण का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से निष्पादित करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(i) उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परीक्षण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत संरक्षित एवं संरक्षणाधीन संस्मारकों के अभिलेखीकरण की कार्यवाही पूर्व की मांति संबंधित क्षेत्रीय पुरातत्व इकाईयों द्वारा की जायेगी।

(i) शेष संस्मारकों, पुरातत्व स्थलों व अवशेषों के संरक्षण का कार्य उन ग्राम पंचायतों व नगरपालिकाओं द्वारा किया जायेगा, जिनकी सीमाओं में ऐसा संस्मारक, पुरातत्व स्थल अथवा अवशेष स्थित है।

2. अभिलेखीकरण में अनुसंधान, प्रकाशन, आडियो/वीडियो रिकार्डिंग, जानकारी प्राप्त करने हेतु विज्ञापन करना, यात्राएं करना व प्राप्त जानकारी की पुष्टि में विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने हेतु उनसे सम्पर्क करना या बैठकें आयोजित करना सम्मिलित है। अभिलेखीकृत जानकारी को सार्वजनिक करना आवश्यक होगा, जिसके लिए प्रकाशन को अतिरिक्त वेबसाइट पर डिजीटल रूप में सूचना उपलब्ध कराई जायेगी।

घटक 2 : Built Heritage का संरक्षण

1. दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में Built Heritage के संरक्षण करने की संस्तुति की गई है और बताया गया है कि पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इमारतों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाये। तदनुसार योजनान्तर्गत क्षेत्रीय पुरातत्व इकाईयाँ, राज्य द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के इतिहास/पुरातत्व विभागों, व Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सहायता से संस्मारकों, पुरातात्विक स्थलों व अवशेषों के संरक्षण की कार्यवाही की जायेगी।
2. योजनान्तर्गत संरक्षण के निमित्त निम्नांकित व्यय की मदें होंगी-
 - (i) संरक्षण (Conservation and Restoration) ।
 - (ii) संरक्षण की स्थिति परिचायक चित्रांकन, मापन, मानचित्रीकरण।
 - (iii) संरक्षित इमारत अथवा स्थान के लिए Buffer Zone विकसित करने अथवा पहुंच मार्ग बनाने हेतु संलग्न भूमि/भदनों का अर्जन।
 - (iv) संरक्षित इमारत अथवा स्थान को दर्शकों के लिए सुविधा सम्पन्न बनाने के कार्य जैसे आस-पास के क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण, सुलभ पैदल या मोटर मार्गों का निर्माण, बिद्युत, पेयजल की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था Perimeter Fencing, सुरक्षा संयंत्रों की स्थापना, इमारत अथवा स्थान से संलग्न क्षेत्र की Landscaping करना, सूचना पट्टी को स्थापित करना, इमारत अथवा स्थान के संबंध में प्रचार-सामग्री तैयार करना आदि।
 - (v) संरक्षित इमारत अथवा स्थान हेतु सुरक्षा, माली, सफाई गाईड, कार्यों की सेवाएं अनुबंध पर प्राप्त करना।
 - (vi) संरक्षण की विधियों में स्थानीय संसाधनों का सृजन करना व आवश्यकतानुसार Centre for Cultural Resources and Training Delhi, Institute of Archaeology, Delhi, National Museum Training Delhi व National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property Lucknow तथा UNESCO से सहायता प्राप्त करना।

- (vii) World Heritage Convention के अनुपालन का कार्य जहां तक उसका संबंध Built Heritage के संरक्षण से हो।
- (viii) State Heritage Regulations व Guideline को विकसित करने से संबंधित कार्य तथा प्रख्यापित हो जाने पर उनके अनुपालन का कार्य।
- (ix) Built Heritage के संरक्षण के संबंध में बैठकों, कार्यशालाओं का आयोजन या उसमें भाग लेना या ऐसे कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- (x) Built Heritage के संबंध में प्रकाशन निकालना या उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

घटक 3 : पुरातत्व अन्वेषण

राज्य के विश्वविद्यालयों में पुरातत्व अन्वेषण करने की तकनीकी क्षमता उपलब्ध है और उनके यदा-कदा वित्तीय सहायता प्राप्त करके खुदाई का कार्य किया जा रहा है। योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर भी पुरातत्व अन्वेषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना प्रस्तावित है, परन्तु यह सहायता केवल राज्य के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को ही अनुमन्य होगी। विश्वविद्यालयों से इस संबंध में प्राप्ता प्रत्येक प्रस्ताव पर यथासंभव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पर्यवेक्षक पुरातत्वविद् की राय प्राप्ता की जानी आवश्यक होगी। योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता परियोजना पद्धति पर दी जायेगी अर्थात् आवर्ती प्रकृति के व्यय के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। योजनान्तर्गत किये गये खुदाई कार्य के परिणामों के प्रसार हेतु बैठक करना, प्रकाशन निकालना या परिणामों का राष्ट्रीय अथवा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतीकरण करने हेतु भी वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्राचीन इमारतों, पुरातात्विक स्थलों व अवशेषों के संरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या-2418 / VI-I / 2006-5 (12) / 2006, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, सी-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. तिलाधिकारी, देहरादून।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वन्दिया)
उप सचिव